

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनेगा बुलेट ट्रेन का टर्मिनस

टर्मिनस के लिए एनएचएसआरसी ने मंगाई निविदाएं

अरुण लाल
patrika.com

मुंबई. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का टर्मिनस बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम (एनएचएसआरसी) ने टर्मिनस के लिए निविदाएं मंगाई हैं। टर्मिनस बनने में कुल लागत 18,00 करोड़ रुपए होगी। यह टर्मिनस भूमिगत बनाया जाना है। इसके ऊपर आईएफएससी भवन बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2017 में बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना का शिलान्यास था।



उन्होंने 15 अगस्त 2022 तक मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की सेवाओं शुरू करने का लक्ष्य रखा था। एमएमआरडीए ने ज्यादा जगह होने का हवाला देते हुए बीकेसी में भवनों के लिए ऊंचाई बढ़ाकर 96मीटर तक करने की अनुमति मांगी थी। इसलिए परियोजना के लिए निविदा में देरी हो गई। वर्तमान में

बीकेसी में भवन की ऊंचाई 61 मीटर है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर आरए राजीव ने पत्रिका को बताया कि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और एनएचएसआरसी ने परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी है।

टर्मिनस में तीन बेसमेंट
यह प्लेटफॉर्म समुद्र तल से 20.7

50 हेक्टेयर में बनेगी आईएफएससी बिल्डिंग

सूत्रों ने बताया कि जिस जमीन पर आईएफएससी बिल्डिंग बनेगी वह 50 हेक्टेयर का होगा। इसमें से लगभग 4.9 हेक्टेयर में बुलेट ट्रेन को स्थान दिया गया है। यह टर्मिनस भूमिगत होगा। एक वरिष्ठ

अधिकारी ने बताया कि टर्मिनस में छह ट्रेनों को एक साथ समायोजित करने के लिए तीन प्लेटफॉर्म होंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई 480 मीटर है, इसमें 16-डिब्बों वाली ट्रेन आ सकेगी।

मीटर नीचे बनाया जाएगा। टर्मिनस में तीन बेसमेंट होंगे- लेवल 1 में टिकटिंग क्षेत्र, यात्री सुविधाएं और निकासी होगी। लेवल 2 में सभी उपयोगिताओं के लिए जगह होगी, जिसमें एसी प्लांट और ट्रेन से संबंधित अन्य सिस्टम शामिल हैं और लेवल 3 में प्लेटफॉर्म होंगे। इस टर्मिनस से मेट्रो2 बी (दहिसर-बीकेसी-मानखुर्द) गलियारे जोड़ा जाएगा। मेट्रो3 भूमिगत (कोलाबा-बांद्रा-सीपेज) नेटवर्क के साथ कनेक्शन काम करना बाकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की थी।

लेकिन काम की गति देखकर पता चलता है कि पहले चरण में इस तिथि पर केवल बिलिमोरा और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है। क्योंकि भूमि अधिग्रहण महाराष्ट्र में एक गंभीर चुनौती है। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को अमल में लाने में थोड़ा और समय लग सकता है।